# उत्तर प्रदेश

# विशिष्ट करेंट अफेयर्स

## जनवरी 2023

## कर्नाटक की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में होगा खेती का सर्वे

• 1 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में अब कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे किया जाएगा। अभी तक प्रदेश में अनुमान के आधार पर रबी, खरीफ व जायद की खेती के क्षेत्रफल, उत्पादन, प्राकृतिक आपदा पर हुए नुकसान संबंधी आँकड़े जुटाए जाते थे।

• कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक चला तो एक साल बाद यह साफ-साफ पता चल सकेगा कि किस ज़िले के किस किसान के पास कितनी खेती है। रबी, खरीफ और जायद में उसने कितने रकबे में क्या बोया और कितना बोया। कितना उत्पादन हुआ। इन सबके अब सटीक आँकड़े मिलेंगे। इनका डिजिटलीकरण भी होगा।

• विदित है कि अभी तक कृषि और राजस्व विभाग द्वारा ज़िला स्तर पर अनुमान पर आधारित प्रदेश की खेतीबारी के आँकड़े जुटाए जाते हैं।

• उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सेटेलाइट मैपिंग की तैयारी की जा रही है। सेटेलाइट से ज़िलेवार, ब्लाकवार हर गाँव में किसानों के खेतों के आकार प्रकार, फसलों की बोवाई, उत्पादन आदि की सटीक जानकारी मिल सकेगी। उसी के अनुरूप किसानों को आवश्यक खाद, रसायन आदि उपलब्ध करवाया जाएगा और फसलों के चयन के बारे में एडवाइजरी दी जाएगी।

• उन्होंने बताया कि अभी तक तो प्रदेश में खेतीबारी का सारा ब्यौरा अनुमान के आकलन पर संकलित होता है। इसमें पूरी तरह साफ-साफ यह पता नहीं चल पाता कि किस किसान ने कितने क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोयी। अतिवृष्टि, बाढ़, पाला, अग्निकांड जैसी आपदा के समय भी सही-सही जानकारी जुटाने में काफी दिक्कत पेश आती है।

• गौरतलब है कि पिछले दिनों कर्नाटक के कृषि व राजस्व विभाग के अफसरों ने अपने राज्य में लागू सेटेलाइट सर्वे के मॉडल का प्रस्तुतीकरण उत्तर प्रदेश में आकर किया। कृषि मंत्री सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह मॉडल पसंद आया। इसे स्वीकृत किया गया और अब इसे उत्तर प्रदेश में संचालित करने की तैयारी की जा रही है।

## वाराणसी में देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट के लिये 200 करोड़ रुपए मंज़ूर

• 1 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस के मंडलायुत्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि बनारस में दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को अब भीड़भाड़ वाले इलाके कैंट स्टेशन से गौदौलिया तक के सफर के लिये रोपवे की सुविधा मिलेगी, जिसके लिये देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे को धरातल पर उतारने के लिये 200 करोड़ रुपए का बजट मंज़ूर हुआ है।

• मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि राज्य में वाराणसी कैंट से गोदौलिया के बीच सड़क किनारे से गुजर रही जनसुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिये बजट की पहली किस्त जनवरी के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी।

• 15 जनवरी के बाद जनसुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिये तैयारी कराई जा रही है। रूट के लिये चिह्नित जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जनवरी महीने में ही शुरू हो जाएगी।

• उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से ज़मीन अधिग्रहण के लिये 173 करोड़ रुपए और जनसुविधाओं की लाइन को शिफ्ट करने के लिये 28 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। शासन ने इस बजट प्रस्ताव को मंज़ूरी देते हुए पहली किस्त जारी करने की पहल भी कर दी है। बजट जारी होने के बाद कैंट से गोदौलिया के बीच सड़क के नीचे से गुजर रही पानी, बिजली सहित अन्य लाइन को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

• ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वे में जलकल, स्मार्ट सिटी, गेल, जल निगम, बीएसएनएल और बिजली विभाग के निर्माण को चिह्नित किया गया है। इसके अलावा कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक 75 किमी लंबे रोप-वे निर्माण के लिये 1.59 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण के लिये चिह्नित है, जिसमें निजी 0.96 हेक्टेयर और सरकारी 0.63 हेक्टेयर है। सर्किट रेट से तय मुआवज़ा के आधार पर निजी ज़मीन पर 72 करोड़ रुपए और सरकारी ज़मीन पर 101 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

• मंडलायुक्त ने बताया कि कैंट, भारतमाता मंदिर, बेसेंट थियेसोफिकल सोसाइटी रथयात्रा, गिरिजाघर और गोदौलिया चौराहे पर स्टेशन और 30 टॉवर बनाए जाने हैं। उन्होंने बताया कि रोपवे परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में मार्च में रोपवे का काम शुरू हो जाएगा।

## उत्तर प्रदेश में अब ऐप से लगेगी मनरेगा श्रमिकों की शत-प्रतिशत हाजिरी

• 2 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि राज्य में अब मनरेगा के कामों में पारदर्शिता के लिये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से शत-प्रतिशत हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

• उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता लाने के लिये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप (एनएमएमएस) के माध्यम से शत-प्रतिशत हाजिरी लगाने की व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग कर रहा है।

• इसी साल से मनरेगा श्रमिकों की शत-प्रतिशत हाजिरी इस ऐप के माध्यम से लगने लगेगी। इसके लिये ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी ज़िलाधिकारियों व ज़िला कार्यक्रम समन्वयक को दिशा-निर्देश दिये हैं।

• आयुक्त ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए लिखा है कि श्रमिकों की उपस्थिति को ऐप के माध्यम से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए और इसकी समीक्षा प्रत्येक सप्ताह विकास खंड स्तर पर की जानी चाहिये।

• उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अभियान (मनरेगा) भारत में लागू एक रोज़गार गारंटी योजना है, जिसे प्रदेश में 7 सितंबर, 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था।

• इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करके ग्रामीण परिवारों के काम करने के अधिकार की कानूनी गारंटी प्रदान करना और उनकी आजीविका को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है।

## गौशालाओं के लिये बनाया जाएगा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल

• 4 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वृहद गौ-आश्रय स्थल के संबंध में प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया और बताया कि गौशाला चलाने के लिये उसकी अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिये एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जाएगा।

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौशालाओं का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाए तथा साथ ही उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी से जोड़ा जाए। इससे गौशालाएँ आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी और गायों के रखरखाव एवं पालन पर आने वाला खर्च खुद उठा सकेंगी।

• गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश में दो से तीन हज़ार गोवंश धारण की क्षमता वाले आश्रय स्थलों के निर्माण को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशाला संचालन के लिये इच्छुक एनजीओ के साथ एमओयू करें और उन्हें आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराएँ।

• योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य सरकार पशु संवर्धन, संरक्षण के लिये सेवाभाव के साथ सतत् प्रयासरत है। गोवंश सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिये सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं तथा पात्र लोगों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाना चाहिये।

• उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही निराश्रित गौ-आश्रय स्थल, सहभागिता योजना और कुपोषित परिवारों के लिये एक गाय की योजना गौ-संरक्षण में काफी प्रभावी है। पूरे प्रदेश में इन तीनों योजनाओं को अभियान चलाकर आगे बढ़ाया जाना चाहिये।

• उन्होंने बताया कि सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गोवंश को पालने वाले किसानों को प्रति गोवंश 900 रुपए मासिक दिये जा रहे हैं। भू-सत्यापन के बाद किसानों को उनका भुगतान किया जाए।

• दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और बेसहारा मवेशियों के नियंत्रण के लिये नस्ल सुधार योजना में तेजी लाई जानी चाहिये। इस योजना के तहत पशुपालक सरकारी पशु अस्पतालों में कृत्रिम गर्भाधान करवा कर मवेशियों की नस्ल को सुधार सकते हैं। इससे दुग्ध का उत्पादन तो बढ़ेगा साथ ही मवेशियों की नई नस्ल भी तैयार हो जाएगी।

## बनारस देगा देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट

• 4 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस नगर निगम के अधिशासी अभियंता अजय राम ने बताया कि धर्म-संस्कृति के लिये विख्यात बनारस अब देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट भी देगा। कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट बनारस के रमना में निर्माणाधीन है।

• अभियंता अजय राम ने बताया कि बनारस के रमना में प्लांट शुरू होने पर प्रति दिन 600 टन कचरे से 200 टन कोयले का उत्पादन हो सकेगा। कचरे से कोयला बनाने वाला यह देश का पहला प्लांट होगा, जिसका निर्माण एनटीपीसी की ओर से कराया जा रहा है। प्लांट में कचरे से कोयला बनाया जाएगा। इसका सफल परीक्षण अक्टूबर 2022 में हो चुका है।

• एनटीपीसी तय मानकों पर प्लांट की एक इकाई का तकनीकी परीक्षण कर रहा है। जून माह के अंत तक प्लांट की पहली इकाई शुरू की जाएगी। उत्पादन के बाद कोयले को आसपास के ज़िलों में संबंधित कंपनियों को बेचा जाएगा।

• वाराणसी में आम दिनों में प्रतिदिन 600 टन तथा खास मौकों पर 800 टन तक कचरा निकलता है। बड़ी ट्रकों से इसे शहर के बाहर कूड़ा निस्तारण प्लांटों तक पहुँचाया जाता है।

• उन्होंने बताया कि तीन साल के ट्रायल पर यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य प्रदेशों में भी प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट निर्माण आगामी 25 साल को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। प्लांट की क्षमता आठ सौ टन से अधिक कचरा प्रसंस्करण की होगी। प्लांट को दिसंबर 2023 तक शुरू करने का लक्ष्य है।

## प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज - एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया

• 13 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज - एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया और टेंट सिटी का उद्घाटन किया।

• इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी से डिब्रूगढ़ तक के सबसे लंबे रिवर क्रूज विश्व पर्यटन मानचित्र पर उत्तर भारत के पर्यटन स्थलों को सामने लाएगा।

• साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में समर्पित की जा रही एक हज़ार करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाएँ पूर्वी भारत में पर्यटन और रोज़गार की सभावनाओं को बढ़ावा देंगी।

• रिवर क्रूज के अनुभव पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इसमें सभी के लिये कुछ न कुछ खास है। आध्यात्मिकता में रुचि रखने वालों के लिये काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली जैसे गंतव्यों को कवर किया जाएगा।

• एक बहुराष्ट्रीय क्रूज अनुभव की तलाश करने वाले पर्यटकों को बांग्लादेश में ढाका से होकर जाने का अवसर मिलेगा तथा जो भारत की प्राकृतिक विविधता को देखना चाहते हैं उनके लिये यह सुंदरबन और असम के जंगलों से होकर गुज़रेगा।

• प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्रूज 25 विभिन्न नदी धाराओं से होकर गुज़रेगा इसलिये उन लोगों के लिये इस क्रूज का विशेष महत्त्व है, जो भारत की नदी प्रणालियों को समझने में गहरी रुचि रखते हैं।

• एमवी गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करते हुए 51 दिनों में लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा करके भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुँचेगा।

• एमवी गंगा विलास में सभी लक्जरी सुविधाओं के साथ तीन डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 सुइट्स हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक पूरी यात्रा के लिये जा रहे हैं।

• एमवी गंगा विलास क्रूज को दुनिया के सामने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये डिजाइन किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों के लिये क्रूज की 51 दिनों की यात्रा की योजना बनाई गई है।

• यह यात्रा पर्यटकों को एक शानदार अनुभव देगी और भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता में शामिल होने का अवसर देगी।

• रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के प्रयास के अनुरूप, इस सेवा के लॉन्च के साथ रिवर क्रूज की विशाल अप्रयुक्त क्षमता का लाभ प्राप्त करना संभव हो जाएगा और यह भारत के लिये रिवर क्रूज टूरिज्म के एक नए युग का सूत्रपात करेगी।

• वाराणसी में टेंट सिटी क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का दोहन करने के लिये गंगा नदी के तट पर टेंट सिटी की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना शहर के घाटों के सामने विकसित की गई

है जो विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद से वाराणसी में रहने की सुविधा प्रदान करेगी और पर्यटकों की बढ़ती संख्या की ज़रूरत को पूरा करेगी।

• इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। पर्यटक आसपास के विभिन्न घाटों से नावों द्वारा टेंट सिटी पहुंचेंगे। टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून तक जारी रहेगी और बारिश के मौसम में नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण तीन महीने के लिये हटा दी जाएगी।

• इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित, हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है और बर्थ को लगभग 3000 डेडवेट टन (डीडब्ल्यूटी) तक के जहाजों को सँभालने के लिये डिजाइन किया गया है।

• प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के सैदपुर, चोचकपुर, जमानिया और बलिया ज़िले के कंसपुर में चार फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में पटना ज़िले के दीघा, नकटा दियारा, बाढ़, पानापुर और बिहार के समस्तीपुर ज़िले के हसनपुर में पाँच सामुदायिक घाटों की आधारशिला रखी गई।

• आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और क्षेत्र में स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार के लिये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा नदी के किनारे 60 से अधिक सामुदायिक घाटों का निर्माण किया जा रहा है। छोटे किसानों, मत्स्य इकाइयों, असंगठित कृषि उत्पादक इकाइयों, बागवानों, फूलों की खेती करने वालों और गंगा नदी के भीतरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कारीगरों के लिये सरल लॉजिस्टिक समाधान प्रदान करके सामुदायिक जेटी लोगों की आजीविका में सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

• प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिये समुद्री कौशल विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में समृद्ध प्रतिभा पूल को तराशने में मदद करेगा और तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक उद्योग में रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

• इनके अलावा प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल में एक जहाज मरम्मत सुविधा और एक एलिवेटेड रोड की आधारशिला भी रखी। पांडु टर्मिनल पर शिप रिपेयर सुविधा से कीमती समय की बचत होगी।

## उत्तर प्रदेश में एससीआर बनाने पर काम शुरू

• 17 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि राज्य में एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने पर काम शुरू हो गया है।

• आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन की दिशा में बाराबंकी में सबसे पहले विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। बाराबंकी एससीआर का हिस्सा है।

• उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर एससीआर बनाया जा रहा है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात ज़िले इसके हिस्सा होंगे।

• प्रस्ताव मिलने के बाद मुख्यमंत्री के समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

• उल्लेखनीय है कि बाराबंकी ज़िला राजधानी से सटा हुआ है। इसलिये इसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से अवैध कालोनियाँ बस रही हैं। बिल्डर यहाँ औने-पौने दामों पर ज़मीन लेकर आवासीय और व्यावसायिक योजनाएँ ला रहे हैं। बाराबंकी में अभी तक विकास प्राधिकरण न होने की वजह से न तो इन कॉलोनियों का नक्शा पास कराया जा रहा है और न ही इस पर रोक लग पा रही है।

## प्रधानमंत्री ने बस्ती ज़िले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया

• 18 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया।

• इस खेल महाकुंभ के दौरान कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि जैसे इनडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेलों में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। इनके अतिरिक्त, निबंध लेखन, पेंटिंग, रंगोली बनाने जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।

• गौरतलब है कि खेल महाकुंभ का पहला चरण 10 से 16 दिसंबर, 2022 तक आयोजित किया गया था और खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी, 2023 तक निर्धारित है।

• इस सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती ज़िले के सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से किया जा रहा है। खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो ज़िला बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करता है और उन्हें खेल को करियर विकल्प के रूप में लेने के लिये प्रेरित करता है। यह क्षेत्र के युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने का भी प्रयास करता है।

• प्रधानमंत्री ने खेल महाकुंभ की व्यापकता की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की है कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से खेलों में भारत की पारंपरिक विशेषज्ञता को एक नया आयाम मिलेगा। करीब 200 सांसद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह के खेल महाकुंभ का आयोजन कर चुके हैं।

• प्रधानमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि इन खेलों के माध्यम से प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत आगे के प्रशिक्षण के लिये चुना जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40,000 एथलीट खेल महाकुंभ में भाग ले रहे हैं।

• प्रधानमंत्री ने बताया कि खेलो इंडिया के माध्यम से 2500 एथलीटों को प्रति माह 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत करीब 500 ओलंपिक संभावित खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कुछ खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए तक की सहायता मिली है।

• देश भर में एक हज़ार से अधिक खेलो इंडिया ज़िला केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं, जिनमें से 750 से अधिक केंद्र पूरे हो चुके हैं। देश भर के सभी खेल के मैदानों की जियो टैगिंग भी की जा रही है, ताकि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत न हो।

• उन्होंने बताया कि सरकार ने पूर्वोत्तर के युवाओं के लिये मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया है और मेरठ, (उत्तर प्रदेश) में भी एक अन्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है।

## उत्तर प्रदेश सरकार देगी 11 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान

• 22 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव रघुनाथ प्रसाद वर्मा ने बताया कि प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के यशभारती सम्मान की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी देश-विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को 'उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान' से नवाज़ेगी।

• उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव रघुनाथ प्रसाद वर्मा की ओर से इस नई सम्मान योजना के लिये 50 लाख रुपए की धनराशि की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

• इस योजना के तहत चार विभूतियों को क्रमश: 11-11 लाख रुपए की राशि के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।

• गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार यश भारती पुरस्कार को दो साल पहले ही बंद कर चुकी है। यश भारती सम्मान के तहत 11 लाख रुपए ऐसी हस्तियों को दिये जाते थे, जिन्होंने देश-विदेश में राज्य का नाम रोशन किया हो। इसकी जगह अब संस्कृति मंत्रलय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरूआत की है।

• उन्होंने बताया कि आगामी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री इस नई पुरस्कार योजना की शुरुआत करते हुए चार विभूतियों को सम्मानित कर सकते हैं।

• उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के लिये जारी शासनादेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश के ऐसे ख्यातिलब्ध महानुभावों, जिन्होंने विभिन्न विधाओं और कार्यक्षेत्रों जैसे- कला एवं संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, शिक्षा, खेल, समाजसेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, ग्राम्य विकास आदि में व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित किए। इसके अलावा इन नए उत्कृष्ट आयामों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया गया हो, उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से अलंकृत किया जाएगा।

• इस सम्मान के लिये नामित व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। विभिन्न विधाओं, कार्यक्षेत्र के ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त महानुभाव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और दीर्घ साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की हो, जिन्होंने देश-विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो।

• राज्य सरकार या केंद्र सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार या सम्मान प्राप्त विभूतियों को इस सम्मान योजना की पात्रता परिधि में नहीं रखा जाएगा।

• योजना के तहत हर साल संस्कृति निदेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर डीएम से नामांकन प्राप्त किये जाएंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों व विधाओं से संबंधित नामांकन संबंधित विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव के माध्यम से और मान्यता प्राप्त संगीत, नृत्य, नाटक, फिल्म व मीडिया की

शिक्षण तथा प्रदर्शन संस्थानों व अन्य स्रोतों से प्राप्त नामांकन भी प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर चयन समिति गठित कर नाम प्रस्तावित कर सकता है।

## कालिंजर दुर्ग में मिली दसवीं शताब्दी की मूर्तियाँ

• 23 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश सामाजिक संस्था कालिंजर शोध संस्थान के निदेशक अरविंद छिरौलिया ने बताया कि राज्य के बांदा ज़िले में ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार से शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी समेत अनेक देवी-देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ मलबे से निकली हैं।

• अरविंद छिरौलिया ने बताया कि कालिंजर दुर्ग में कई छोटे-बड़े सरोवर और तालाब हैं। उन्हीं में से एक कोटि तीर्थ सरोवर है, जहाँ मूर्तियाँ व पत्थरों पर बनीं कलाकृतियाँ मिली हैं, जो नवीं और दसवीं शताब्दी की हैं।

• उन्होंने बताया कि कुछ पत्थरों पर देवी-देवताओं की नक्काशी है। इसमें भगवान विष्णु, गणेश, लक्ष्मी जी, पार्वती जी की प्रसन्न मुद्रा वाली भी मूर्तियाँ हैं। शिवलिंग को छोड़कर अधिकतर मूर्तियाँ खंडित हैं।

• कालिंजर दुर्ग के इतिहास के जानकार समाजसेवी विवेक शुक्ला ने बताया कि 1986 में दुर्ग तक जाने के लिये रोड बनाई जा रही थी। तब भी खोदाई के दौरान इसी तरह से मूर्तियाँ निकली थीं। उन्हें पुरातत्त्व विभाग ने संरक्षित कर राजा अमान सिंह महल में रखवा दिया था।

• दुर्ग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि तब 282 केएफ नंबर से 305 तक की मूर्तियाँ और तोप के गोले निकले थे। उनको पुरातत्त्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया था। इसके अलावा 1960 में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने कालिंजर दुर्ग को अपने संरक्षण में लिया था।

• ज्ञातव्य है कि कालिंजर काफी प्राचीन दुर्ग है, जहाँ गुप्त काल से लेकर बुंदेलों तक का शासन रहा है। यहाँ पर पूर्व में भी निर्माण कार्य के दौरान इस तरह की मूर्तियाँ मिलती रही हैं।

• विदित है कि तीर्थ सरोवर कालिंजर दुर्ग का सबसे सुंदर और पौराणिक स्थल है। पूरा दुर्ग भारतीय पुरातत्त्व विभाग के अधीन है। सरोवर की दीवार से मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ सहेजकर इसका निर्माण दोबारा कराया जा रहा है। सरोवर के चारों तरफ की प्राचीन दीवारों पर देवी-देवताओं की मूर्तियाँ व कलाकृतियाँ हैं।

• कालिंजर इतिहास से जुड़े अरविंद छिरौलिहा ने बताया कि भारत पर राज करने वाला छठवाँ शासक औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य उसका शासन रहा, इसे मूर्ति भंजक कहा जाता था। वह हिन्दू धर्म की मूर्तियों को खंडित करवा देते थे।

• वर्ष 1812 से 1947 के बीच ब्रिटिश शासन के समय पर हिन्दू धर्म से जुड़ी स्मृतियों को भी नष्ट करने का काम किया जाता था। कोर्ट तीर्थ सरोवर काफी प्राचीन है, लेकिन इसके चारों तरफ की दीवारें अंग्रेजों द्वारा बनाई गईं थीं। तब दीवार के पीछे यह मूर्तियाँ भी दबा दी गईं थीं, जिससे कि सनातन धर्म और हिन्दू धर्म जागृत न हो सके।

• कालिंजर दुर्ग नीलकंठ मंदिर के राजपुरोहित पंडित शंकर प्रताप मिश्रा ने बताया कि कोटि तीर्थ सरोवर में सभी तीर्थों का जल मिला है। ऐसे में इस सरोवर के जल से यहीं पर विराजमान भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक करने से एक हज़ार गायों के दान का पुण्य मिलता है। खास तौर से कार्तिक पूर्णिमा पर जलाभिषेक अधिक फलदायी माना जाता है।

## मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जबकि प्रदेश के अन्य सात विभूतियाँ पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित

• 25 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के लिये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों 'पद्म पुरस्कारों'की घोषणा की। इनमें उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जबकि प्रदेश के अन्य सात विभूतियों को पद्म श्री अवार्ड के लिये चुना गया है।

• वर्ष 2023 के लिये राष्ट्रपति ने तीन द्वय मामलों (एक द्वय मामले में, पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है) सहित 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है।

• सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएँ हैं और विदेशियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं।

• समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को नागरिक मामले में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार लिये चुना गया है।

• पद्म श्री पुरस्कार के लिये चयनित उत्तर प्रदेश के सात विभूतियों में राधा चरण गुप्ता, दिलशाद हुसैन, अरविंद कुमार, मनोरंजन साहू, रित्विक सान्याल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और उमा शंकर पांडे शामिल हैं।

• राधा चरण गुप्ता और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन और रित्विक सान्याल को कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, मनोरंजन साहू को चिकित्सा के क्षेत्र में तथा उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये पद्म श्री अवार्ड हेतु चुना गया है।

• गौरतलब है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल हैं। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में प्रदान किये जाते हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।

• यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिये जाते हैं।

• असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म विभूषण', उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म भूषण'और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म श्री'से सम्मानित किया जाता है।

• ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोहों में प्रदान किये जाते हैं जो आमतौर पर हर साल मार्च/अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाते हैं।

## देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश

• 27 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि महज़ आठ साल में 47 करोड़ नए बिजली कनेक्शन देने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ताओं वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु हैं।

• विदित है कि उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 74 करोड़, महाराष्ट्र में करीब 2.40 करोड़ और तमिलनाडु में करीब 2.20 करोड़ है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल उपभोक्ताओं की संख्या करीब तीन करोड़ बताई जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश से 23 से 25 लाख कम है।

• पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि बीते आठ साल में प्रदेश के 8 करोड़ से अधिक परिवार ढिबरी और लालटेन युग से बाहर निकल आए हैं। इस अवधि में प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन का रिकॉर्ड भी बना है।

• ज्ञातव्य है कि वर्ष 2014 तक राज्य में कुल करीब 42 करोड़ उपभोक्ता थे, वहीं वर्ष 2014 से नवंबर 2022 के बीच राज्य में 1.8 करोड़ नए उपभोक्ताओं के घरों में बिजली पहुँची। बिजली के साथ ही इन परिवारों में पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पहुँच गए।

• एम. देवराज ने बताया कि राज्य के लोगों के रहन-सहन में सुधार को ऐसे भी समझा जा सकता है कि वर्ष 2014 में बिजली की अधिकतम मांग 12327 मेगावाट रिकॉर्ड की गई थी, जो 2022 में 26589 मेगावाट पहुँच गई। बिजली के कनेक्शन दोगुने से अधिक हुए तो खपत भी उसी गति से बढ़ गई।

• प्रदेश सरकार ने हर घर को बिजली कनेक्शन देने का अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 2017 से अब तक एक करोड़ 47 लाख 90 हज़ार नए कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इसमें बड़ी भूमिका 'सौभाग्य योजना'के तहत कनेक्शन देने की रही।

• उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने बताया कि वर्ष 2017 से 2021 के बीच 'सौभाग्य योजना'के तहत प्रदेश में 18 लाख कनेक्शन दिये गए थे। इस योजना में अधिक कनेक्शन देने पर भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत भी किया था।

• उन्होंने बताया कि प्रदेश में 'रिवैम्प्ड योजना'के तहत बिजली व्यवस्था को और बेहतर किया जा रहा है। बिजली उत्पादन से लेकर वितरण तक कई योजनाओं पर काम शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध बिजली मिलेगी।

## गोरखपुर के 'पनियाला' को मिला जीआई टैग

• 29 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की हाईपावर कमेटी ने जिन 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग के लिये अनुमति दी है, उनमें पनियाला भी शामिल है।

• जीआई टैग की अनुमति मिलने से गोरखपुर के लच्छीपुर और आस-पास के गाँवों में पैदा होने वाले पनियाला का स्वाद अब देश-दुनिया तक पहुँचेगा। नष्ट होते जा रहे पनियाला के पेड़ संरक्षित किये जाएंगे, पनियाला के बगीचे तैयार होंगे और उसके फल के खट्टे-मीठे स्वाद का लोग आनंद उठाएंगे।

• ज्ञातव्य है कि पनियाला आकार और रंग में जामुन से मिलता-जुलता है तथा इसका स्वाद खट्टा-मीठा है।

• उत्तर प्रदेश स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड की ई-पत्रिका के मुताबिक स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह कहाँ का पेड़ हैं। संभावना इस बात की ज़रूर है कि यह मूलत: उत्तर प्रदेश में ही पाया जाने वाला फल है। पनियाला की वास्तविक उपज भले ही कहीं हो, लेकिन गोरखपुर महानगर के उत्तरी इलाके में स्थित लच्छीपुर से लेकर नकहा रेलवे स्टेशन के बीच इसके कई बागीचे थे। पहले लच्छीपुर की पहचान ही पनियाला थी। लंबे समय तक इस गाँव के लोगों की आय का ज़रिया पनियाला और अमरूद के फल थे।

• उल्लेखनीय है कि पनियाला 60 से 90 रुपए किलो तक बिक जाता है। कभी-कभी 100-150 रुपए किलो तक भी बिकता है। एक पेड़ से 4000 रुपए की आय हो जाती है।

• वर्ष 2011 से 2018 के बीच पं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में हुए कई शोध में यह बात सामने आई कि पनियाला गुणों की खान है। शोध के अनुसार इसके पत्ते, छाल, जड़ों एवं फलों में बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है। पेट से जुड़े रोगों में पनियाला काफी लाभकारी होता है। दाँतों और मसूढ़ों में दर्द, इनसे खून आने, कफ, निमोनिया और खराश आदि के इलाज़ में भी इसका प्रयोग होता रहा है। इसे संरक्षित कर लंबे समय तक रखा भी जाता है।

• विदित है कि पं. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के शिक्षक प्रो. वी.एन. पांडेय के निर्देशन में उनकी शोध छात्रा निहारिका पांडेय द्विवेदी ने भी पनियाला पर अपना शोध पूरा किया था। वर्ष 2015 में निहारिका का शोध सामने आया, जिसे विशेषज्ञों ने खूब सराहा। पनियाला में सेहत के लिहाज से कई फायदेमंद तत्त्व पाए गए।